गैस की सप्लाई हुई प्रभावित

सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया

नई दिल्ली,10 मार्च. भारत के कई राज्यों में इन दिनों कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हो रही हैं. इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने गैस की सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए एक्ट 1955 लागू कर दिया है.

गैस संकट क्यों पैदा हुआ?- हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हुई है. अस्थिरता के कारण तेल और गैस की आपूर्ति में बाधा आई है. भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है. रिपोर्टों के अनुसार भारत की एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई का बड़ा भाग पश्चिम एशिया से आता है. देश के कई राज्यों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई कम होने की शिकायतें सामने आई हैं. इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं.

गैस की सप्लाई को 4 हिस्सों में बांटा गया- सरकार ने मौजूदा संकट को देखते हुए गैस की

पहली कैटेगरी -घरेलू गैस और सीएनजी- घरों में इस्तेमाल होने वाली गैस और वाहनों की सीएनजी को पूरी सप्लाई दी जाएगी.

दूसरी कैटेगरी - खाद बनाने वाले कारखाने-उर्वरक उद्योग को लगभग 70प्रतिशत गैस दी जाएगी ताकि खेती पर असर न पड़े.

तीसरी कैटेगरी - बड़े उद्योग- बड़े उद्योगों को उनकी जरूरत के अनुसार करीब 80 प्रतिशत गैस दी जाएगी.

दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 60 रुपये बढ़कर करीब 913 रुपये हो गई है. वहीं 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भी पहले बढ़ोतरी की जा चुकी है. इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है.

सरकार ने प्राकृतिक गैस पर लगाया एस्मा

सरकार ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आयी बाधाओं को देखते हुए देश में रसोई गैस (एलपीजी) का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर आवश्यक वस्तु अधिनियम (एस्मा) लगा दिया है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 के अनुसार, घरेलू पीएनजी की आपूर्ति, परिवहन के लिए सीएनजी की आपूर्ति, एलपीजी उत्पादन, और पाइपलाइन कॉम्प्रेशर फ्यूल तथा अन्य अनिवार्य पाइपलाइन परिचालन जरूरतों को प्राथमिकता सेक्टर-1 में रखा गया है.

सिलेंडर की बुकिंग 25 दिन बाद

नई दिल्ली, 10 मार्च. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोमवार रात घोषणा की थी कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग अब 21 दिन की बजाय 25 दिन के अंतराल पर करायी जा सकेगी.

तेल विपणन कंपनियों ने होटल, रेस्त्रां तथा अन्य गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर की अपनी जरूरत सरकार द्वारा गठित समिति के समक्ष रखने के लिए ई-मेल आईडी जारी कर दिये हैं.

सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण आपूर्ति में आयी कमी को देखते हुए एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति पर लगाम लगाया है.

घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर देने का फैसला किया गया. गैर-घरेलू उपभोक्ताओं में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को आपूर्ति जारी रहेगी. अन्य गैर-घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरत पर विचार करने सरकार ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है.

इस बात से संतुष्ट होने पर कि उपभोक्ता को रसोई गैस की अनिवार्य जरूरत है और उसे आपूर्ति की जानी चाहिये, समिति इसकी अनुमति देगी.

देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्टों में बताया कि समिति में इंडियन ऑयल के के. शैलेंद्र, भारत पेट्रोलियम के टी.वी. पांडियन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ध्रुव कपिल शामिल हैं. पोस्ट में उनकी ई-मेल आईडी भी जारी की गयी है.

शेयर बाजारों में लौटी खुशी की लहर

809 अंक पर चढ़ा सेंसेक्स

252 अंक की बढ़त पर रहा निफ्टी

मुंबई, 10 मार्च. विदेशों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों में तेजी देखी गयी. बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 809.57 अंक चढ़कर 78,375.73 अंक पर खुला.

हालांकि बाद में इसकी तेजी कुछ कम हुई और खबर लेकर जाते समय यह 327.78 अंक यानी 0.42 प्रतिशत की मजबूती के साथ 77,893.94 अंक पर रहा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 252.75 अंक की बढ़त में 24,280.80 पर खुला. खबर लिखे जाते समय यह 98.70 अंक यानी 0.41 प्रतिशत ऊपर 24,126.75 अंक पर था.

आईटी और तेल एवं गैस को छोड़कर अन्य सभी सेक्टरों के सूचकांक हरे निशान में रहे. ऑटो, वित्त, फार्मा, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद और स्वास्थ्य सेक्टरों के सूचकांकों में ज्यादा तेजी दर्जकी गयी. सेंसेक्स की कंपनियों में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एलएंडटी, भारतीय स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा इंडिगो और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर ऊपर चल रहे थे. रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस, एयरटेल, टीसीएस और बजाज फाइनेंस में फिलहाल गिरावट है.

रुपया 39 पैसे टूटा, 92.21 प्रति डॉलर के नए निचले स्तर पर

मुंबई, 10 मार्च. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 10 प्रतिशत से ज्यादा उछाल के कारण रुपये पर सोमवार को भारी दबाव रहा और यह 39 पैसे टूटकर 92.21 रुपये प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ. पिछले कारोबारी दिवस पर भारतीय मुद्रा 17.50 पैसे फिसलकर 91.82 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई थी. रुपये पर शुरू से ही दबाव रहा. यह 40.50 पैसे की गिरावट में 92.2250 रुपये प्रति डॉलर पर खुला. एक समय यह 92.35 रुपये प्रति डॉलर तक उतर गया था. बाद में रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से डॉलर बेचने से यह 92.15 रुपये प्रति डॉलर तक मजबूत हुआ.

भारत का खाद्य निर्यात 5 लाख करोड़ के पार : गोयल

नई दिल्ली 10 मार्च. केंद्रीय मंत्री ने उद्योग और किसानों से प्रोसेस्ड फूड व वैल्यू एडिशन बढ़ाने का आह्वान किया, एफटीए से 38 देशों के बाजारों तक पहुंच का फायदा उठाने पर जोर. भारत का कृषि और खाद्य उत्पादों का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है और अब यह सालाना करीब 5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पियूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि इस उपलब्धि के साथ भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यातक बन गया है. उन्होंने खाद्य, कृषि और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से जुड़े लोगों से अपील की कि वे मिलकर भारत को कृषि और प्रोसेस्ड फूड निर्यात में दुनिया का नंबर एक देश बनाने के लक्ष्य की दिशा में काम करें.

गोयल ने कहा कि यह उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन के अनुरूप हैं, जिसमें भारत को 'दुनिया की फूड बास्केट' बनाने का लक्ष्य रखा गया है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में भारत ने नौ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) किए हैं, जिनसे 38 विकसित देशों के बाजारों तक भारतीय उत्पादों की पहुंच बनी है. इससे भारतीय निर्यातकों को नए अवसर मिले हैं और देश वैश्विक वैल्यू चेन से तेजी से जुड़ रहा है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन व्यापार समझौतों के दौरान सरकार ने घरेलू हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की है. किसानों, मछुआरों और एमएसएमई के हितों को ध्यान में रखते हुए डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी उत्पादों को कोई रियायत नहीं दी गई है.

उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में भारत के प्रोसेस्ड फूड, फल, दाल, सब्जियों और अनाज के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है. सरकार का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में वैल्यू एडिशन बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना और भारत को वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत खिलाड़ी बनाना है.

गोयल ने बताया कि 2014 से 2025 के बीच भारत के कृषि और खाद्य निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. इस अवधि में प्रोसेस्ड फूड का निर्यात चार गुना, फल और दालों का निर्यात तीन गुना, प्रोसेस्ड सब्जियों का निर्यात चार गुना और कोको का निर्यात तीन गुना बढ़ा है. वहीं अनाज का निर्यात लगभग दोगुना हो गया है और चावल के निर्यात में भी करीब 62 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

ऑडी ने शुरू की नए एसयूवी एसक्यू8 की बुकिंग

मुंबई, 10 मार्च. जर्मन लग्जरी कार निर्माता ऑडी ने मंगलवार को भारत में अपने नये एसयूवी ऑडी एसक्यू8 के लिए बुकिंग शुरू करने की घोषणा की. कंपनी ने एक विज्ञप्ति में बताया कि ग्राहक 5,000 रुपये की शुरुआती राशि देकर ऑडी इंडिया की वेबसाइट पर या %मायऑडी कनेक्ट% ऐप से बुकिंग कर सकते हैं. इसमें चार लीटर का वी8 टीएफएसआई इंजन है.

चावल नरम, गेहूं मजबूत और दालों, खाद्य तेलों में घट-बढ़

नई दिल्ली, 10 मार्च. घरेलू थोक जिंस बाजारों में मंगलवार को चावल के औसत भाव टूट गये. वहीं, गेहूं में तेजी रही. चीनी के भाव कमोबेश स्थिर रहे जबकि दालों और खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा. औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत नौ रुपये घटकर 3,847 रुपये प्रति क्विंटल रह गयी. गेहूं तीन रुपये महंगा हुआ और 2,813 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा. आटे के भाव में टिकाव रहा. दाल-दलहनों में तुअर दाल औसतन 32 रुपये प्रति क्विंटल सस्ती हुई. मसूर दाल की कीमत 22 रुपये और चना दाल की 20 रुपये घट गयी. मूंग दाल में नौ रुपये की गिरावट रही. वहीं, उड़द दाल दो रुपये प्रति क्विंटल मजबूत हुई.

सोना 1230 रुपए महंगा, चांदी में 4 प्रतिशत उछाल

नई दिल्ली, 10 मार्च. अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच निवेशकों की सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ी दिलचस्पी, एमसीएक्स पर सोना-चांदी की कीमतों में तेज उछाल.

सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोना और चांदी की कीमतों में मंगलवार को जोरदार तेजी देखने को मिली. वैश्विक बाजारों में बढ़ती अनिश्चितता, अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण निवेशकों का रुझान फिर से बुलियन की ओर बढ़ गया है. इसी का असर घरेलू बाजार में भी दिखाई दिया, जहां चांदी की

कीमतों में एक ही दिन में 9,250 रुपये की बड़ी छलांग दर्ज की गई और इसका भाव बढ़कर करीब 2.77 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया. वहीं सोने की कीमत भी 1,230 रुपये की तेजी के साथ 1.62 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी बुलियन में मजबूत खरीदारी देखी गई. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के समय निवेशक आम तौर पर सोना-चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख करते हैं.

पश्चिम एशिया में तनाव और ऊर्जा कीमतों में संभावित उछाल ने महंगाई की आशंकाओं को बढ़ा दिया है, जिससे निवेशकों की चिंता भी बढ़ी है. हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर नीति और डॉलर की चाल आने वाले समय में सोना-चांदी की कीमतों की दिशा तय कर सकती है.

मोबाइल पर दिखेगा राशन कार्ड का पूरा हिसाब

नई दिल्ली, 10 मार्च. उमंग ऐप के 'मेरा राशन' फीचर से कार्डधारक अब घर बैठे राशन की पात्रता, पुरानी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और नजदीकी सरकारी राशन दुकान की लोकेशन आसानी से देख सकेंगे.

सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी को पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ी डिजिटल सुविधा शुरू की है. अब राशन कार्ड धारकों को अपने कोटे का हिसाब जानने के लिए सरकारी दफ्तरों या राशन की दुकान के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. मोबाइल पर एक ऐप के जरिए यह सारी जानकारी कुछ ही सेकंड में मिल जाएगी.सरकार के मल्टी-सर्विस प्लेटफॉर्म उमंग में अब 'मेरा राशन' फीचर जोड़ा गया है. इस सुविधा के जरिए यूजर्स सिर्फ अपना राशन कार्ड नंबर डालकर यह जान सकते हैं कि सरकारी योजना के तहत उन्हें कितना गेहूं, चावल, चीनी या अन्य अनाज मिलने का अधिकार है.

लंबित मामलों में बैंकों की प्रगति की समीक्षा

नई दिल्ली,10 मार्च. वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम. नागराजू ने एक समीक्षा बैठक में दिवाला कानून के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में दाखिले और समाधान के लिए लंबित मामलों में प्रगति की समीक्षा की और बैंकों से दिवाला प्रक्रिया में फंसी सम्पत्ति के अधिकतम मूल्य की वसूली के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया.

बैंकों के वसूल नहीं होने वाले कर्जों के मामलों की दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत

सुनवाई एनसीएलटी करता है और उसके निर्णयों पर अपील के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण की व्यवस्था है. वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में डीएफएस के वरिष्ठ अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शीर्ष प्रबंधन और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल थे. बैठक में कहा गया कि सी हितधारकों के समन्वित प्रयास से 20 उच्च बकाये वाले ऋण खातों का समाधान एनसीएलटी के माध्यम से किया गया है. विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए प्रवेश के लिए लंबित शीर्ष 20 खातों और समाधान के लिए लंबित 10 खातों की विस्तृत समीक्षा की गई गयी. बैठक में बैंकों को सलाह दी गई कि वे संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने, वसूली में सुधार करने और समयबद्ध उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए लंबित मामलों के समाधान में सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाएँ.

समाचार विशेष

नीतीश के जाते ही बदल जाएगा सब कुछ...

पटना. ये करीब-करीब तय हो गया है कि बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा. फॉर्मूला उलटा हुआ नजर आएगा जब जदयू से दो डिप्टी सीएम होंगे. वहीं बिहार विधानमंडल में चिराग पासवान की ताकत बढ़ेगी और उनके एक मंत्री और बनेंगे. यही नहीं चिराग को एक एमएलसी वाली सीट और मिलेगी. कुल मिलाकर मुश्किल विरोधी राजद के लिए होगी, उन्हें अब अपनी पूरी रणनीति नए सिरे से बनानी होगी. इसकी कई वजहें हैं.

राजद नेताओं ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं कि राज्यसभा चुनाव के बाद उनके तेवर बदलेंगे और रणनीति भी. हाल के सालों में राजद और खास कर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के प्रति ज्यादा आक्रामक रुख नहीं अपनाया. वजह साफ थी कि नीतीश कुमार के रहते उसे तीसरी बार उनके साथ सत्ता में आने की उम्मीद लगी हुई थी. पिछले दो बार के बाद राजद को ऐसा लग रहा था कि नीतीश का मन बदल सकता है. लेकिन अब नीतीश बिहार की राजनीति नहीं करेंगे. जाहिर है राजद के लिए भी ये एक झटका है.

अब राजद बदलेगी बिहार में अपनी रणनीति- पार्टी के एक प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इसी मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर कहा कि हम और हमारे नेता लालू प्रसाद यादव बीजेपी की विचारधाराओं के खिलाफ ही लड़ते आए हैं. हम अब भी उसी दिशा की तरफ चलेंगे. लेकिन हां, ये तय है कि अब हमारी रणनीति बदलेगी क्योंकि ड्राइविंग सीट पर नीतीश कुमार के बदले बीजेपी होगी. जाहिर है कि बीजेपी के लिए हमारी रणनीति भी बिल्कुल नई होगी. आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन भी इसी ट्रैक पर नजर आए. हालांकि राजद का ध्यान फिलहाल राज्यसभा की पांचवी सीट पर है, जिसके लिए पार्टी ने अमरेंद्र धारी सिंह को उम्मीदवार बनाया है.

बिहार की राजनीति सच में बदलने जा रही

ये तय मान कर चलिए कि बिहार में राजनीति अब सही मायनों में बदलेगी. क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा एक ऐसे ट्रैक पर चली जिसमें विकास छोड़ कर और कोई बात नहीं होती थी, क्योंकि उनका सबकुछ बिहार ही था. लेकिन बीजेपी को पूरे देश में अपनी हनक बरकरार रखनी है. ऐसे में बिहार में सियासत कुछ इसी तर्ज पर देखने को मिल सकती है. हालांकि लोगों के मन में ये संशय भी है कि सत्ता तो नहीं लेकिन क्या बिहार में फिर से 90 जैसी राजनीति देखने को मिलेगी?

उद्धव ठाकरे फिर बनेंगे एमएलसी?

महाराष्ट्र की राजनीति में आया बड़ा मोड़, संजय राउत ने ठोकी मजबूत दावेदारी

मुंबई. शिवसेना (उद्धव गुट) ने गठबंधन की मजबूरियों के चलते राज्यसभा सीट के लिए शरद पवार को समर्थन देने के बाद अब विधान परिषद चुनाव में महाविकास आघाडी (एमवीए) के लिए पक्की मानी जा रही सीट पर उद्धव ठाकरे को उम्मीदवार बनाए जाने की दावेदारी लगभग पेश कर दी है.

शिवसेना (उद्धव गुट) के सांसद संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे विधानमंडल में विपक्ष की एक मजबूत आवाज हैं और उनका दोबारा निर्वाचित होना जरूरी है. सभी विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं की भी यही इच्छा है कि उद्धव ठाकरे फिर से विधान परिषद में जाएं. राउत ने कहा कि एमवीए आगामी विधान परिषद चुनाव में कम से कम एक सीट जीत सकती है और इसके लिए चुनाव निर्विरोध कराने की कोशिश होनी चाहिए.

एमवीए में शिवसेना के 20 विधायक हैं, जो गठबंधन में सबसे बड़ा दल है. इसके बाद कांग्रेस के 16 और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 10 विधायक हैं. राउत ने संवाददाताओं से कहा कि उद्धव ठाकरे विधानमंडल और परिषद में एक मजबूत आवाज हैं. हम सभी चाहते हैं और सभी वरिष्ठ विपक्षी नेताओं की भी इच्छा है कि उद्धव ठाकरे दोबारा विधानमंडल में जाएं. राउत ने हालांकि यह भी स्पष्ट किया कि विधान परिषद चुनाव की घोषणा होने के बाद उचित समय पर एमवीए के सभी घटक दल मिलकर फैसला लेंगे.

राज्यसभा उम्मीदवारी न मिलने से पहले ही नाराज

विधान परिषद चुनावों से पहले शिवसेना (यूबीटी) द्वारा अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारने की नयी कोशिश से राकांपा (शप) और कांग्रेस को झटका लग सकता है. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार न भेज पाने से पहले ही नाराज है. इस बीच, आदित्य ठाकरे ने भी परोक्ष रूप से राज्यसभा चुनाव में पार्टी की ओर से उम्मीदवार उतारने का मौका नहीं मिल पाने पर निराशा जताई. उन्होंने कहा कि विधायकों की संख्या के हिसाब से हमारी पार्टी सबसे बड़ी थी, लेकिन सीट सबसे कम विधायकों वाली पार्टी राकांपा को दे दी गई.

पेज एक का शेष

8.80 लाख करोड़ की मंजूरी

अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिलने से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी. इससे विदेशी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को भी आकर्षित करने में मदद मिलेगी. नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने बताया कि देश में फिलहाल 164 हवाई अड्डे संचालित हैं और सरकार का लक्ष्य 2047 तक करीब 350 हवाई अड्डे स्थापित करने का है. पिछले 10 वर्षों में हवाई अड्डों, यात्रियों और विमान बेड़े में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिसे सरकार नागरिक उड्डयन क्षेत्र में किए गए सुधारों और उड़ान योजना का परिणाम मानती है. वहां से दुबई, अबु धाबी और कोलंबो के लिए उड़ानों का परिचालन भी होता है और बुनियादी ढांचा पूरी तरह से तैयार है. कई विमान सेवा कंपनियों ने वहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने में रुचि दिखायी है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली-फरीदाबाद-बल्लभगढ़-सोहना उपमार्ग से जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक नई सड़क निर्माण परियोजना के संशोधित बजट को मंजूरी दे दी है. बैठक में 3630.77 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति दी गई. 31.42 किमी लंबा यह कॉरिडोर दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ेगा.

विशेष | सहयोगियों की 'बगावत' से उड़ी भाजपा की नींद, चुनाव से पहले मचा बवाल!

...तो असम में हिमंता के साथ हो जाएगा खेला?

गुवाहाटी. असम में 2026 के चुनाव की तैयारी हो चुकी है, लेकिन सत्ताधारी खेमे में सीट-शेयरिंग को लेकर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. सहयोगी दलों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं ने रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है. हालात ऐसे हैं कि कई चुनाव क्षेत्रों में गठबंधन सहयोगियों के बीच 'फ्रेंडली फाइट' होने की संभावना बढ़ गई है.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार विकास के वादों के साथ मैदान में है. जबकि दूसरी ओर उसके सामने अपने सहयोगी दलों, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट को खुश रखने की

बड़ी चुनौती है.

क्यों बढ़ीं भाजपा की मुश्किलें?- साल 2014 से भाजपा की वफादार सहयोगी रही असम गण परिषद इस बार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है. 2021 के चुनावों में एजीपी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 26 पर अकेले और तीन पर भाजपा के साथ गठबंधन किया था. पार्टी नौ सीटें जीतने में कामयाब रही. इस बार एजीपी के जमीनी कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि पार्टी को ज्यादा सीटों पर मौका दिया जाए, जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

फ्रेंडली फाइट बिगाड़ेगी भाजपा का खेल!- मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने संकेत दिया है कि एजीपी के साथ शुरुआती बातचीत शुरू हो गई है. हालांकि, जब उनसे सहयोगियों की बढ़ती मांगों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि उन्हें किसी भी फॉर्मल मांग के बारे में पता नहीं है, लेकिन उन्होंने 'फ्रेंडली फाइट' की संभावना से इनकार नहीं किया. गठबंधन की सबसे मुश्किल स्थिति बोडोलैंड इलाके में सामने आ रही है. यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए अपनी आक्रामक रणनीति की घोषणा की है. इनमें से 15 बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इलाके में हैं और छह इसके बाहर हैं. सबसे बड़ी समस्या यह है कि बीएफपी और पीपीएल के बीच कड़वाहट कम होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है. दोनों पार्टियों ने साफ कर दिया है कि वे न तो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी और न ही सीट-शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमत होंगी.

कांग्रेस ने बना लिया है सबसे बड़ा प्लॉन

दूसरी ओर सत्ता से बाहर कांग्रेस की लीडरशिप वाला विपक्षी गठबंधन खुद को एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है. चार बड़ी विपक्षी पार्टियों ने 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए हाथ मिलाया है और एक जॉइंट कैंपेन शुरू करने का प्लान बनाया है. असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट गौरव गोगोई ने गठबंधन की एकता पर जोर देते हुए कहा कि सभी सहयोगी जल्द ही पूरे राज्य में मिलकर कैंपेन मीटिंग करेंगे. गोगोई ने कहा कि हमारे पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं और ये 30 दिन असम के भविष्य के लिए बहुत जरूरी हैं.